



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 मई, 2021 ई०

बैशाख 14, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-6

संख्या 98/टी०सी०-1216/XXVII(6)/2016/2021

देहरादून, 04 मई, 2021

### अधिसूचना

सा०प०नि०-09

राज्यपाल, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (सं० 21 वर्ष 2019) की धारा 38 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

#### उत्तराखण्ड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली, 2021" है।

परिभाषाएँ

- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;
  - (क) "अधिनियम" से "अविनियमित" निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (सं० 21 वर्ष 2019) अभिप्रेत है;
  - (ख) "प्रपत्र" से इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;
  - (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
  - (घ) स्वप्रेरणा से संज्ञान "Suo motu cognizance" से किसी सरकारी अधिकरण, न्यायालय या अन्य राज्य या केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा अपने स्वयं के संदेह के आधार पर किया गया कार्य अथवा स्वयं के पहल पर किये गये कार्य अभिप्रेत है;

**सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां  
एवं कर्तव्य**

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं।

(1) यदि सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रकरण से संबंधित सम्पत्ति अथवा जमाकर्ता के नाम से प्राप्त सम्पत्ति या जमाकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्राप्त की गयी सम्पत्ति की पहचान की जरूरत है, तो सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 31 की उपधारा(1) के प्रावधानानुसार पुलिस प्राधिकारियों से या आवश्यकता अनुसार किसी अन्य प्राधिकारी अथवा लोक अधिसूचना के द्वारा आम जनता से संबंधित सम्पत्ति या परिसम्पत्ति के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(2) जहां पर सूचना उपनियम (1) में उल्लिखित लोक अधिसूचना के माध्यम से जनता से प्राप्त की गयी हो, ऐसी स्थिति में पुलिस प्राधिकारी से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दो मुख्य स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाएगा।

**जांच या अन्वेषण  
के दौरान निहित शक्ति**

4.

(3) अतिरिक्त सूचनाओं को एकत्र करने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी का यह मन्तव्य है कि जमाकर्ता की कुछ अतिरिक्त सम्पत्तियों को सम्बद्ध किये जाने की आवश्यकता है, तो वह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ऐसा कर सकेगा।

(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 4 के अंतर्गत जांच या अन्वेषण की कार्यवाही जब तक एवं अन्यथा आवश्यक न हो, सक्षम प्राधिकारी जांच या अन्वेषण किये जाने हेतु निम्नलिखित नोटिस निर्गत कर सकता है अर्थात्:-

(i) प्रपत्र 'क' में कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने विषयक नोटिस;

(ii) यदि आवश्यक हो, तो प्रपत्र 'ख' में अतिरिक्त सूचना प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस;

(iii) जमाकर्ता या अन्य व्यक्तियों तथा गवाहों के व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु प्रपत्र 'ग' के रूप में अंतिम नोटिस।

(2) जहां तक संभव हो, औपबन्धिक सम्बद्धीकरण विषयक आदेश में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जायेगा:-

(i) शिकायत का पूर्ण विवरण;

(ii) जमाकर्ता अथवा वित्तीय इकाई का पूर्ण विवरण;

(iii) पुलिस से प्राप्त जांच रिपोर्ट;

(iv) यदि कोई नियामक हो, तो उससे प्राप्त रिपोर्ट;

(v) जनता से प्राप्त शिकायतें;

(vi) कार्यवाही का पूर्ण विवरण, ऐसी सम्पत्ति को सम्बद्ध किये जाने का कारण, सम्बद्धीकरण के प्रभावी होने की तिथि;

(vii) जारी अथवा तामिल नोटिस की प्रति तथा वितरण का प्रमाण, यदि कोई हो;

(viii) जांच का सारांश;

(ix) सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, बैंक खाता संख्या, सम्बद्ध धनराशि, शेयर एवं बॉण्ड सहित प्रतिभूतियां, सम्बद्ध चल सम्पत्तियां, ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य और अचल सम्पत्ति की स्थिति में भूमि की मात्रा, सर्वेक्षण संख्या और ऐसी सम्पत्ति की सीमायें तथा ऐसी सम्पत्ति धारक का नाम;

(x) निष्कर्ष और;

(xi) साक्ष्य (प्रमाण का साक्ष्य या सबूत संलग्न करें)।

(3) सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 4 के अंतर्गत अभिलिखित (रिकॉर्ड) किया जायेगा और सम्बन्धित कार्यवाही हेतु विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

फरार व्यक्तियों से संबंधित शक्तियाँ

5. जहां सक्षम प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है अथवा वह इस बात के लिये संतुष्ट है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई विचारणीय है, वह फरार है अथवा अपने को छिपा रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी अथवा उसकी सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिहित न्यायालय में लिखित में रिपोर्ट देगा।

सम्पत्तियों को जब्त करने की शक्ति

6. जहां सक्षम प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है अथवा वह इस बात के लिये संतुष्ट है कि जो सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत सम्बद्ध की जानी है उसे छिपाया जा सकता है, स्थानान्तरित अथवा इस ढंग से उपयोग किया जा सकता है जिससे अधिनियम के उद्देश्य पूर्ण न हो सके, ऐसी स्थिति में वह पुलिस अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति जब्त करने का निदेश दे सकता है अथवा जहां ऐसी सम्पत्ति को जब्त करना व्यवहारिक न हो, व उस सम्पत्ति को फ्रीज (रोक) करने का आदेश दे सकता है जिससे सम्पत्ति न तो स्थानान्तरित की जा सकती है, न ही किसी अन्य रूप से निपटाई जा सकती हैं।

विधि व्यवसायी एवं अन्य की नियुक्ति की शक्तियाँ

7. सक्षम प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियोजन विभाग, विधि व्यवसायियों, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या किसी अन्य व्यक्ति की सेवाओं को, परिसम्पत्तियों की प्राप्ति एवं कब्जे के लिये जिनकी सेवायें आवश्यक हो, उपयोग कर सकता है,

परिसम्पत्तियों की फोरेंसिक या डिजिटल ऑडिट, मूल्यांकन अथवा विक्रय हेतु एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की सरकार की शक्ति

8. (1) सरकार निम्नलिखित की सूची को सूचीबद्ध एवं अधिसूचित करेगी:-  
(क). परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं प्रत्याशित क्रेताओं को परिसम्पत्तियों के विक्रय हेतु एजेंसियां तथा  
(ख). धन के लेन-देन की लेखा परीक्षा हेतु फोरेंसिक ऑडिटर्स एवं डिजिटल ऑडिटर्स

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन, परिसम्पत्तियों के विक्रय एवं धन के लेन-देन की फोरेंसिक एवं डिजिटल ऑडिट हेतु उक्त सूचीबद्ध एजेंसियों एवं ऑडिटर्स की सेवाओं का प्रयोग किया जायेगा।

(3) जब तक राज्य सरकार उक्त एजेंसियों को सूचीबद्ध नहीं करती तब तक सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार धन के लेन-देन की लेखा परीक्षा हेतु इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा सूचीबद्ध फोरेंसिक ऑडिटर्स या डिजिटल ऑडिटर्स की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

सम्बद्ध सम्पत्तियों को मुक्त किये जाने के समय मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त किया जाना

9. अभिहित न्यायालय अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सम्बद्ध सम्पत्तियों को मुक्त किये जाने के संबंध में उचित मूल्य जमा किये जाने का निर्णय कम से कम दो सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं के रिपोर्ट के आधार पर देगा।

**प्रपत्र 'ख'**  
**(नियम 4 देखें)**  
**अतिरिक्त सूचना हेतु नोटिस**

सेवा में

महोदय/महोदया

विषय-एम/एस

संदर्भ: प्रपत्र 'क' में नोटिस

दिनांक:.....

प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि जो सूचनायें या रिपोर्ट प्राप्त हुयी है, उसके अनुसार प्रश्नगत वित्तीय इकाई या जमाकर्ता की गतिविधियां अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानानुसार संज्ञेय है।

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी को धारा 3 के उल्लंघन में जमा योजनाओं में अनाधिकृत रूप से जमा योजनाओं में हुयी चूक की जांच या पूछताछ के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक सिविल कोर्ट में निहित शक्तियों के समान ही शक्ति प्राप्त है। अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:-

(क). वित्तीय इकाई द्वारा संचालित जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा योजना या चिट फण्ड योजना या जमाओं की पुनर्दायगी में चूक या ऐसी जमाओं के सापेक्ष विशिष्ट सेवाओं का वादा आदि के संबंध में अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण या कतिपय विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी निर्देशित करता है, तदनुसार उक्त सूचना तुरन्त उपलब्ध करायें:-

i-

ii-

iii-

iv-

(ख). आपसे अपेक्षा की जाती है कि मेरे कार्यालय में दिनांक.....समय.....पर स्वयं या इसके लिए लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित समय पर अपने गतिविधियों या कार्यों के समर्थन में या प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कोई दस्तावेज, खातों या कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करें।

यदि आप अधोहस्ताक्षरी के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना और अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। सुनवाई हेतु प्रदत्त अवसर के समय उपस्थित न होने या साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकित या एक पक्षीय आदेश हो सकता है।

**नोट:- (\*जो लागू न हो, उसे काट दें।)**

दिनांक:

**प्रपत्र 'ख'**  
(नियम 4 देखें)  
अतिरिक्त सूचना हेतु नोटिस

सेवा में

महोदय/महोदया

विषय-एम/एस

संदर्भ: प्रपत्र 'क' में नोटिस

दिनांक:.....

प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि जो सूचनायें या रिपोर्ट प्राप्त हुयी है, उसके अनुसार प्रश्नगत वित्तीय इकाई या जमाकर्ता की गतिविधियां अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानानुसार संज्ञेय है।

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी को धारा 3 के उल्लंघन में जमा योजनाओं में अनाधिकृत रूप से जमा योजनाओं में हुयी चूक की जांच या पूछताछ के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक सिविल कोर्ट में निहित शक्तियों के समान ही शक्ति प्राप्त है। अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:-

(क). वित्तीय इकाई द्वारा संचालित जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा योजना या चिट् फण्ड योजना या जमाओं की पुनर्दायगी में चूक या ऐसी जमाओं के सापेक्ष विशिष्ट सेवाओं का वादा आदि के संबंध में अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण या कतिपय विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी निर्देशित करता है, तदनुसार उक्त सूचना तुरन्त उपलब्ध करायें:-

i-

ii-

iii-

iv-

(ख). आपसे अपेक्षा की जाती है कि मेरे कार्यालय में दिनांक.....समय.....पर स्वयं या इसके लिए लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित समय पर अपने गतिविधियों या कार्यों के समर्थन में या प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कोई दस्तावेज, खातें या कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करें।

यदि आप अधोहस्ताक्षरी के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना और अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। सुनवाई हेतु प्रदत्त अवसर के समय उपस्थित न होने या साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकित या एक पक्षीय आदेश हो सकता है।

नोट:- (\*जो लागू न हो, उसे काट दें।)

दिनांक:

प्रपत्र 'ग'  
(नियम 4 देखें)  
अंतिम नोटिस

सेवा में

महोदय/महोदया

विषय-एम/एस

संदर्भ: प्रपत्र 'क' में नोटिस।

प्रपत्र 'ख' में नोटिस।

दिनांक:.....

प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि जो सूचनायें या रिपोर्ट प्राप्त हुयी है, उसके अनुसार प्रश्नगत वितीय इकाई या जमाकर्ता की गतिविधियां अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानानुसार संज्ञेय हैं।

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी को धारा 3 के उल्लंघन में जमा योजनाओं में अनाधिकृत रूप से जमा हुयी चूक की जांच या पूछताछ के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक सिविल कोर्ट में निहित शक्तियों के समान ही शक्ति प्राप्त है। अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:-

(क). प्रपत्र 'क' संख्या-.....दिनांक.....के माध्यम से आपसे पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु आपके द्वारा वांछित विवरण एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

और/या

(ख). प्रपत्र 'ख' संख्या-.....दिनांक.....के माध्यम से आपसे कुछ अतिरिक्त दस्तावेज व विवरण उपलब्ध कराने तथा मेरे कार्यालय में दिनांक.....समय.....पर स्वयं या आपके द्वारा लिखित में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित समय पर अपने गतिविधियों या कार्यों के समर्थन में या प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कोई दस्तावेज, खातें या कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गयी थी, किन्तु आप मेरे समक्ष वांछित विवरण व दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं हुये हैं।

(ग). आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत आपको वांछित विवरण व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है और/या अपेक्षित विवरण व दस्तावेजों के साथ मेरे समक्ष दिनांक.....समय.....को उपस्थित होने का अवसर दिया जाता है। यदि आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना और अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कार्यवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी। सुनवाई हेतु प्रदत्त अवसर के समय उपस्थित न होने या साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में सर्वोत्तम निर्णय प्रभावित या एक पक्षीय हो सकता है।

नोट:- (\*जो लागू न हो, उसे काट दें।)

दिनांक:

**प्रपत्र 'क'**  
**(नियम 4 देखें)**  
**कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु नोटिस**

सेवा में

महोदय/महोदया

विषय-एम/एस

प्राप्त सूचना या रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वित्तीय इकाई या जमाकर्ता ऐसी गतिविधियों में शामिल है, जो अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानानुसार संज्ञेय है। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी या समक्ष प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी को धारा 3 एवं 4 के उल्लंघन में जमा योजनाओं में अनाधिकृत रूप से जमा में हुई चूक की जांच या पूछताछ के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक सिविल कोर्ट में निहित शक्तियों के समान ही शक्ति प्राप्त है। अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

प्रश्नगत मामले के संबंध में आपसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है:-

- (क). वित्तीय इकाई का पूर्ण विवरण, इकाई का पंजीकरण, जमा स्वीकार किये जाने विषयक नियामक की अनुमति यदि कोई हो, विशिष्ट पहचान संख्या या पंजीकरण और पैन नम्बरों (PAN Numbers) के साथ।
- (ख). प्रवर्तकों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों, भागीदारों, प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों आदि का विवरण, विशिष्ट पहचान संख्या या पंजीकरण और पैन नम्बरों (PAN Numbers) के साथ।
- (ग). नवीनतम ऑडिट की गयी बैलेंस शीट और दाखिल किये गये लाभ और हानि खाते।
- (घ). नियामक का विवरण एवं पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रति, जमा स्वीकार करने विषयक गतिविधि को करने की अनुमति।
- (ङ). जमा योजना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें, जिसके तहत जनता से जमा एकत्र की जा रही है।
- (च). स्वीकार की गयी जमाओं के साथ ही जमाकर्ताओं की सूची, ब्याज की दर, परिपक्वता तिथि, मूलधन एवं ब्याज के प्रतिसंदाय (Repayment) की शर्तें, अन्य कोई वादे या आश्वासन या देय कमीशन आदि।
- (छ). जमाओं के प्रतिसंदाय में हुयी चूक का पूर्ण विवरण, यदि कोई हो या चूक के विवरण के साथ ही ऐसी जमाओं के सापेक्ष किसी विशिष्ट सेवा का वादा।
- (ज). चूक में शामिल कुल धनराशि एवं इससे प्रभावित जमाकर्ताओं की कुल संख्या, यदि कोई हो।
- (झ). चूक का कारण, यदि कोई हो
- (ञ). चूक के पश्चात् धनराशि वापसी के संबंध में उठाए गए या प्रस्तावित कदम।
- (ट). वित्तीय इकाई के बैंक खातों का नवीनतम शेष राशि के साथ पूर्ण विवरण।

तदनुसार आप उपर्युक्त सूचीबद्ध आपके बिन्दुओं के संबंध में विधिवत् रूप से प्रमाणित पूर्ण विवरण मेरे कार्यालय में दिनांक .....समय.....पर स्वयं या इसके लिए लिखित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को निर्धारित समय पर अपने कार्य या गतिविधियों के समर्थन में या प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कोई दस्तावेज, खाते या कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करें।

यदि आप अधोहस्ताक्षरी के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना और अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कार्रवाई कर दी जायेगी। सुनवाई हेतु प्रदत्त अवसर के समय उपस्थित न होने या साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकित या एक पक्षीय आदेश हो सकता है।

नोट:- (\*जो लागू न हो, उसे काट दें।)

दिनांक:

आज्ञा से,  
अमित सिंह नेगी,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 98/XXVII(6)/TC 1216/2016-2021, dated May 04, 2021 for general information:

No. 98/XXVII(6)/TC 1216/ 2016-2021

Dated Dehradun, May 04, 2021

### NOTIFICATION

In exercise of the power conferred under Section 38 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), the Governor makes the following rules, namely:-

#### **The Uttarakhand Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2021**

#### **Short title and commencement**

1. (1) These rules may be called the "Uttarakhand Banning of Unregulated Deposit Schemes Rule, 2021".
- (2) It shall come into force at once.

#### **Definitions**

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires-
  - (a) 'Act' means the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No.21 of 2019);
  - (b) 'Form' means the form appended to these rules;
  - (c) 'Government' means the Government of Uttarakhand State;
  - (d) 'suo motu cognizance' means an action taken by a Government agency, court or other State or Central authority on its own apprehension or official acts of its own initiative.
- (2) The word and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

#### **Powers and duties of the Competent Authority**

3. (1) If the Competent Authority or an officer appointed to assist the Competent Authority is satisfied that the facts of the case necessitate identification of the properties or assets acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker, the Competent Authority or the officer appointed to assist the Competent Authority, may procure such details from Police authorities utilizing the provisions of sub-section (1) of Section 31 of the Act or any other authority as deemed fit or from public through a public notification seeking the details of properties or assets.
- (2) Where the information is received from the public through the public notification mentioned in sub-rule (1) an advertisement may be released in two prominent local news paper within a period of fifteen days of receipt of report from the police Authorities informing that a prima facie case exists.
- (3) If the Competent Authority, after collecting additional information, is of the opinion that some additional properties of the deposit taker require to be attached, it may do so in accordance with Section 7 of the Act.

**Powers vested while  
conducting  
investigation or inquiry**

4. (1) Unless and otherwise felt essential, to conduct investigation or inquiry under sub-section (4) of Section 7, while conducting investigation or inquiry, the following notices may be issued by the Competent Authority, namely:-

- (i) notice for initiation of action in Form 'A';
- (ii) notice for additional information, if any, required in Form 'B';
- (iii) final notice for personal attendance of deposit taker or other persons and witnesses in Form 'C'.

(2) The order of provisional attachment shall contain to the extent possible, the following:

- (i) Complete details of the Complaint;
- (ii) Complete details of the deposit taker or financial entity;
- (iii) inquiry report from the police;
- (iv) report received from regulator if any;
- (v) complaints received from public;
- (vi) Complete details of the proceedings, reasons for attaching such properties, effective date of attachment;
- (vii) copies of the notices issued or served and delivery proof, if any;
- (viii) summary of the findings;
- (ix) details of property attached, bank account numbers, amount attached, securities including shares and bonds, attached movable property, approximate value of such property, and in case of immovable property the extent of land, survey numbers and boundaries of such property and name of the title holder of such property;
- (x) conclusion; and
- (xi) evidences (attach the evidences or proof).

(3) The proceedings of the Competent Authority shall record the proceedings under sub section (4) of Section 7 of the Act and shall follow due process of law diligently.

**Powers relating to  
absconding persons**

5. Where the Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority is satisfied or has sufficient reasons to believe that a person in respect of whom action is contemplated under this Act has absconded or is concealing himself, the Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority shall make a report in writing to the Designated Court for further course of action.

**Power to seize  
properties**

6. Where the Competent Authority or officers appointed to assist the competent Authority is satisfied or has sufficient reason to believe that any property which is liable to be attached under the Act is likely to be concealed, transferred or dealt in any manner which will result in defeating the purpose of the Act, it may direct the police officer to seize such property or where it is not practicable to seize such property make an order to freeze such property and it shall not be transferred or otherwise disposed of or dealt with.

**Power to appoint legal practitioner and others**

7. The Competent Authority or an officer appointed to assist the Competent Authority shall be entitled to use the services of the Department of Prosecution, legal practitioners or chartered accountants or any other persons whose services are necessary for possession and realization of the assets.

**Power of Government to empanel agencies for forensic or digital audit, valuation or sale of assets**

8. (1) The Government shall empanel and notify the following list of:-

(a) Agencies for valuation of assets and for assisting in selling of assets to prospective buyers; and

(b) Forensic auditors and digital auditors for audit of money trail.

(2) The Competent Authority shall utilize the services of said empanelled agencies and auditors for valuation of assets, for selling of assets and for forensic and digital audit of money trail.

(3) The Competent Authority may also utilize the services of Forensic Auditors or digital Auditors empanelled by the Indian Banks' Association for Audit of Money trail till the State empanels said agencies, wherever required.

**Valuation reports to be obtained while releasing properties attached**

9. The Designated Court while according permission to deposit the fair value of the property in lieu of the attachment under sub-section (1) of Section 17 of the Act may obtain valuation reports from at least two empanelled Valuers while releasing properties.

## Form 'A'

(see rule 4)

## Notice for initiation of action

To,

Sir/Madam

Sub: M/s

Based on the information or reports received it is prima facie apparent that the subject financial entity or deposit taker is involved in the act which are cognizable under the provisions of section 3 of the Act.

The Competent Authority or the officers appointed to assist the Competent Authority are under sub section (3) and (4) of the Section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court under the Code of Civil procedure, 1908 while conducting investigation or inquiry in respect of the unauthorized deposit schemes of defaults under the deposit schemes in contravention of Section 3 or 4.

In exercise of the powers under the Act the following order is passed:-

In connection with the subject, in question you required to submit the following documents:

- (a) Complete Details of financial entity, registration of the entity, permissions to accept deposits from regulations if any, including unique identification number or Registration and PAN numbers.
- (b) Complete Details of the promoters, Managing Directors, Directors, Partners, Management persons etc, including unique identification number or Registration and PAN numbers.
- (c) Complete Latest audited Balance Sheet and profit and loss accounts filed.
- (d) Complete Details of the Regulator and the copy of registration certificates, permissions to undertaker the activity of deposit taking.
- (e) Produce full details of the Scheme of Deposits under which deposits are being collected from public.
- (f) List of the Depositors along with deposit accepted, rate of interest, maturity date, terms of repayment of interest and principle, any other promises or assurances or commissions payable etc.
- (g) Complete Details of defaults if any in repayment of deposit or any specified service promised against such deposit along with date of default.
- (h) Total amount in default and number of depositors affected, if any.
- (i) Reasons for default, if any
- (j) Steps taken or proposed to repay the amount after default
- (k) Details of the Bank accounts of the financial entity with latest balance in the accounts.

You are hereby required to submit the full details listed above and duly attested, to my office on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ either in person or through representative duly authorized in writing in this behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter.

In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or ex-parte order.

(Note: \*Strike whichever is not applicable)

Date:

**Form 'B'**  
(see rule 4)

**Notice for additional information**

To \_\_\_\_\_

Sir/Madam,

Sub:M/s

Ref: Notice in Form-A

Dated: \_\_\_\_\_

Based on the information or reports received it is prima facia apparent that the activities of the financial entity or deposit taker, in question is are cognizable under the provisions of section 3 of the act.

The Competent Authority or the officers appointed to assist the Competent Authority under sub section (3) and (4) of section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court under the code of civil procedure, 1908 while conduction investigation or inquiry in respect of the unauthorised deposit schemes or defaults under the deposit schemes under section 3 of the act. In exercise of the power under the Act the following order is passed.

(A) The undersigned directs to provide certain further details or clarifications or additional information listed here below are required in connection with the deposit scheme\* or chit funds scheme\* or defaults in repayment\* of deposit or any specified service promised against such deposit, under the deposit scheme/s by the financial entity, provide such information immediately.

i.

ii.

iii.

iv.

(B) You are hereby required to attend my office on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ either in person or through representative duly authorised in writing in this behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter.

(C) In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a best judgment assessment or an ex parte order.

(Note: Strike whichever is not applicable)

Date:

**Form 'C'**  
(see rule 4)  
**Final Notice**

To \_\_\_\_\_

Sir/Madam,

Sub:M/s

Ref: Notice in Form 'A' Dated: \_\_\_\_\_

Notice in Form 'B' Dated: \_\_\_\_\_

Based on the information or reports received it is prima facia apparent that the activities of the financial entity or deposit taker are cognizable under the provisions of section 3 of the Act.

The competent authority or the officers appointed to assist the Competent Authority under sub section (3) and (4) of section 7 of the act have the same power as vested in a civil court under the code of civil procedure, 1908 while conduction investigation or inquiry in respect of the unauthorised deposit schemes or defaults under the deposit schemes under section 3 of the act. In exercise of the power under the act the following order is passed.

(A) As per notice in form A calling complete details and documents no \_\_\_\_\_ dated you were asked to submit the details and documents but you have failed to submit the details and document called for.

**And/or**

(B) As per notice in form B you were asked to furnish certain additional documents or details and also to attend my office on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ either in person or through a representative duly authorised in writing on his/her behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter,

But you have failed to appear before me along with the details and document called for.

(C) In view of you not complying with the orders of the under signed, a final opportunity is been given to you to submit the details and documents required for and/or appear before me along with the details and documents required for on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ failing which it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a best judgment assessment or an ex parte order

(Note: Strike which ever is not applicable)

Date

By order and etc.

By Order,  
AMIT SINGH NEGI,  
Secretary.